दैनिक जागरण

धर्म और विज्ञान साथ जुड़ने के बाद ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं

छल-कपट भरे चुनाव

विभिन्न दलों की चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों के साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जैसी खबरें लगातार आ रही हैं उससे यह नहीं लगता कि हमारे राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के अनुरूप चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तो यही अधिक लग रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता की कहीं कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब इस संहिता का निर्माण खुद उन्होंने किया है। समस्या केवल यह नहीं है कि चुनाव प्रचार के मान्य तौर-तरीकों की जमकर अनदेखी की जा रही है, बल्कि यह भी है कि छल-कपट से चुनाव जीतने कोशिश हो रही है। पैसे बांटकर चुनाव जीतने की प्रवृत्ति किस तरह बढ़ती जा रही है, इसका प्रमाण यह है कि निर्वाचन आयोग अभी तक करीब 32 सौ करोड़ रुपये की नकदी जब्त कर चुका है। निःसंदेह यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी वह सारी रकम जब्त करने में समर्थ हुए होंगे जो मतदाताओं को बांटने के लिए जमा की गई। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी सख्ती के चलते पैसे बांटने का सिलसिला थम गया है। एक समय पैसे बांटकर चुनाव जीतने की प्रवृत्ति केवल दक्षिण भारत में दिखती थी, लेकिन अब वह सारे देश में नजर आ रही है।

चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों में गिरावट का एक अन्य प्रमाण यह भी है कि नेता अपने विरोधियों की आलोचना करने में बदजुबान हुए जा रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन लगता नहीं कि इसका असर पड़ रहा है। नेता एक-दूसरे की आलोचना करते समय केवल भाषा की मर्यादा ही नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि वे जाति-मजहब को भी भुना रहे हैं। कहीं जातीय आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश हो रही है तो कहीं मजहबी आधार पर। पता नहीं क्यों राजनीतिक दल यह साधारण सी बात समझने को तैयार नहीं कि अगर कुछ जातियों को गोलबंद करने की कोशिश की जाएगी तो शेष जातियां स्वतः गोलबंद होने की कोशिश करेंगी या फिर कोई उन्हें ऐसा करने के लिए कहेगा? इस बार एक और खराब बात यह भी देखने को मिल रही है कि नेता झूठ का सहारा लेने में लगे हुए हैं। वे ऐसी-ऐसी बातें कहने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं जिनका कहीं कोई आधार ही नहीं। इससे भी खराब बात यह है कि यदि कभी उनके झूठ को चुनौती दी जाती है तो वे यह कहकर बच निकलने की कोशिश करते हैं कि चुनाव प्रचार की गर्मी में गलत बात निकल गई। केवल इतना ही नहीं, नेता फर्जी खबरों का भी सहारा ले रहे हैं। ऐसा करके वे फर्जी खबरें गढ़ने वालों को बल ही प्रदान कर रहे हैं। वे सामाजिक माहौल में कटुता घोलने का भी काम कर रहे हैं। यह सही है कि निर्वाचन आयोग को और अधिकार संपन्न बनाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन आखिर राजनीतिक दलों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर वे नियम-कानूनों की अनदेखी करते हुए लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ताक पर रखेंगे तो फिर भारतीय लोकतंत्र और साथ ही चुनाव प्रक्रिया के मान-सम्मान की रक्षा कैसे होगी?

व्यावसायिक शिक्षा

उत्तराखंड में स्किल इंडिया को प्रोत्साहित करने का दावा सरकार भले ही करे, लेकिन हकीकत में इसे लेकर सरकारी तंत्र गंभीर नहीं है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना इसका बड़ा उदाहरण है। इस योजना के तहत राज्य में करीब दस हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी है। वर्षों से इसकी कवायद चल रही है, लेकिन यह अंजाम तक नहीं पहुंच रही। नए शैक्षिक सत्र में भी इसे शुरू किया जा सकेगा, इसे लेकर सरकार और शिक्षा महकमे में इच्छाशक्ति की कमी बनी हुई है। राज्य के सभी 13 जिलों में 200 राजकीय इंटर कॉलेजों में उक्त योजना प्रारंभ होनी है। कुल नौ ट्रेड में 45 कॉलेजों में दो-दो ट्रेड और शेष में एक-एक ट्रेड शुरू किए जाएंगे। कृषि, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, आइटी, मल्टी स्किलिंग, प्लंबर, रिटेल, पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार ट्रेड के लिए कुल 255 प्रयोगशाला बनेंगी और इन ट्रेड का प्रशिक्षण देने को 255 शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस कार्य के लिए व्यावसायिक पार्टनर का चयन किया जाना है। पार्टनर के चयन की प्रक्रिया तकनीकी अड़चनों में फंसकर रह गई है। सरकार ने तय किया है कि ई-निविदा के माध्यम से पार्टनर का चयन होगा। इसके माध्यम से यह कार्य बीते जनवरी माह में पूरा होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सका। चार महीने बाद अब ई-निविदा के लिए निर्वाचन आयोग से गुहार लगाई गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस मामले में शिक्षा महकमा अपने हाथ बंधे हुए महसूस कर रहा है। अब आयोग से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा योजना में यह लेटलतीफी महकमे के कामकाज में पेशेवर नजरिये के अभाव को बयां कर रही है। इसी वजह से बीते चार वर्षों से योजना लटकी है। प्रदेश में भाजपा सरकार भी दो वर्ष पूरे कर चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया का अहम हिस्सा व्यावसायिक शिक्षा को लेकर ढुलमुल रवैया बरकरार है। उक्त योजना जितनी जल्द शुरू होगी, छात्र-छात्राओं का इसका तेजी से लाभ मिल सकेगा और संबंधित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

और गहराता आतंक का साया

संजय गुप्त

भारत के लिए यह अच्छा संदेश नहीं कि बांग्लादेश के बाद एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में आइएस के आतंक ने दस्तक दे दी

पिछले रविवार को श्रीलंका में दिल दहलाने वाले बम धमाकों के बाद दक्षिण एशिया एक बार फिर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इन धमाकों में करीब ढाई सौ लोग मारे गए और पांच सौ लोग घायल हुए। इस भीषण आतंकी हमले के लिए स्थानीय संगठन नेशनल तौहीद जमात यानी एनटीजे को जिम्मेदार माना गया। यह भी साफ हो गया है कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इस्लामिक स्टेट यानी आइएस ने एनटीजे के एक आत्मघाती दस्ते के जरिये ये भीषण हमले कराए। 2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद श्रीलंका पहली बार किसी बड़े आतंकी हमले से दो-चार हुआ है। इस हमले का असर न केवल पीड़ित परिवारों, बल्कि वहां के सुरक्षा तंत्र और अर्थव्यवस्था पर भी लंबे समय तक रहने वाला है। श्रीलंका और आतंकी हमलों के अंदेशे से ग्रस्त है। वहां एनटीजे के आतंकियों की धरपकड़ के बीच विस्फोटक सामग्री भी बरामद हो रही है। साफ है कि एनटीजे ने अपना सघन जाल फैला लिया था। समझना कठिन है कि लिट्टे जैसे खूंखार संगठन से जूझ चुका श्रीलंका एनटीजे के उभार को क्यों नहीं भांप पाया? ईस्टर के दिन जिस तरह तीन चर्चों को निशाना बनाया गया और पश्चिमी देशों के नागरिकों से गुलजार रहने वाले तीन होटलों में भी विस्फोट किए गए उससे स्पष्ट है कि आतंकी ईसाई समुदाय के साथ विदेशियों को भी मारना चाहते थे। लगता है वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय और खास तौर पर पश्चिमी देशों को संदेश देना चाह रहे थे।

श्रीलंका में हुआ हमला कुछ समय पहले न्यूजीलैंड में हुई उस आतंकी वारदात का जवाब माना जा रहा है जिसमें मस्जिदों पर गोलियां बरसाकर 49 लोगों की जान ले ली गई थी। एक श्वेत चरमपंथी के इस हमले ने न्यूजीलैंड को सन्न कर दिया था, क्योंकि इसके पहले यह देश ऐसे आतंक का गवाह नहीं बना। सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित न्यूजीलैंड तो इस आतंकी हमले से जल्द उबर सकता है, लेकिन श्रीलंका जैसे विकासशील और राजनीतिक रूप से अस्थिर देश के लिए इतने बड़े हमले का सही तरह सामना करना मुश्किल है। इसलिए और भी, क्योंकि वह सामाजिक बिखराव से मुक्त नहीं हो पाया है। लिट्टे के खात्मे के बाद अशांति और अस्थिरता के दौर से निकलने की कोशिश में लगे श्रीलंका के लिए यह हमला एक बड़ी मुसीबत बनकर आया है। एक तो सामाजिक अशांति का खतरा है और दूसरे, पर्यटन उद्योग की कमर टूटने का। आतंकी हमले के बाद श्रीलंका के वे होटल खाली से हो गए हैं जहां अच्छी-खासी संख्या में विदेशी पर्यटक रुकते थे। श्रीलंका आतंकी हमले से बच सकता था, अगर उसने भारत की ओर से भेजी गई खुफिया सूचना पर सतर्कता बरती होती। इस खुफिया सूचना में साफ कहा गया था कि आतंकी चर्चों के साथ भारतीय उच्चायोग को भी निशाना बना सकते हैं। कोई नहीं जानता कि इस खुफिया सूचना की अनदेखी क्यों की गई? यह पर्याप्त नहीं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एनटीजे और एक अन्य चरमपंथी संगठन पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह बात अब और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब सरकारें समय पर सही निर्णय नहीं लेतीं तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज कोई भी देश आतंकवाद संबंधी खुफिया सूचनाओं की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं जब कहीं पर आतंकी हमले संबंधी खुफिया जानकारी की अनदेखी की गई हो या फिर पर्याप्त चौकसी न बरती गई हो। अभी कुछ दिनों पहले पुलवामा में हुआ आतंकी हमला खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की चूक का ही नतीजा माना जा रहा है। इससे संतुष्ट हुआ जा सकता है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को श्रीलंका में आतंकी हमले की भनक लग गई, लेकिन इसकी जरूरत बनी हुई है कि भारतीय सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां अतिरिक्त चौकसी बरतें। इस जरूरत की पूर्ति तो सभी देशों को करनी होगी कि आतंकवाद से निपटने में कोई कोताही न बरती जाए।

अवधेश राजपूत

श्रीलंका में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस्लामिक स्टेट की ओर जाना स्वाभाविक है, लेकिन इस हमले ने पश्चिमी देशों के इस दावे की पोल खोल दी कि पश्चिम एशिया से आइएस का खात्मा हो गया है। हालांकि सीरिया में आइएस के आतंक को नियंत्रित करने में पश्चिमी देशों को कामयाबी मिली है, लेकिन उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि आइएस पूरी तरह खत्म हो गया है। सच तो यह है कि न तो सीरिया जिहादी आतंकवाद से मुक्त हो सका है और न ही अफगानिस्तान तालिबान, अलकायदा और आइएस के आतंक से। दुनिया के अन्य देश जिन जिहादी संगठनों से ग्रस्त हैं उनमें आइएस प्रमुख है। आइएस एक आतंकी संगठन से अधिक मानसिकता है और उसे खत्म करना आसान नहीं। इस मानसिकता ने दुनिया के अलग-अलग देशों के मुस्लिम समाज के एक वर्ग को अपने प्रभाव में ले लिया है, जिनमें पढ़े-लिखे लोग भी शामिल हैं। जब तक कट्टरता की यह मानसिकता पूरी तरह समाप्त नहीं की जाती तब तक आइएस जैसे संगठनों को खत्म करना संभव नहीं। कट्टरता के इसी प्रसार के कारण मुस्लिम समाज पर सवाल उठने लगे हैं। तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी इसे समझ रहे हैं, फिर भी उनकी आवाज आइएस जैसे संगठनों के आगे दब रही है। स्पष्ट है कि चरमपंथी और आतंकी संगठनों के खिलाफ और ऊंचे स्वर में एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। आखिर आइएस जैसे आतंकी संगठनों को आतंक फैलाने के लिए धन कहां से मिल रहा है? क्या कारण है कि पढ़े-लिखे मुस्लिम युवा भी इस आतंकी संगठन में शामिल होने को तैयार हैं? इन सवालों के जवाब खोजना ही होंगे। आज पूरा मुस्लिम जगत आतंक के ठप्पे से आहत है, लेकिन आम मुसलमान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों को पालने-पोसने और उनकी खुली पैरवी करने वाले देशों के समक्ष असहाय है। उनका उन धार्मिक-राजनीतिक नेताओं पर भी कोई बस नहीं जो अपने सियासी लाभ के लिए मजहबी कट्टरता को हवा देते हैं। भारत में भी अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेला जाता है। इस राजनीति के कारण ही मजहबी कट्टरता के खिलाफ उपयुक्त माहौल बनाना मुश्किल होता है।

देखना यह होगा कि श्रीलंका में नेशनल तौहीद जमात की अनदेखी क्यों हुई? श्रीलंका में हुए आतंकी हमले ने दक्षिण एशिया में आतंक के खतरे को गहराने का काम किया है। एक ऐसे समय जब कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतें पहले से ही भारत की चिंता का कारण हैं तब श्रीलंका में नेशनल तौहीद जमात की कारगुजारी इस चिंता को और बढ़ाने वाली है। भारत के लिए यह अच्छा संदेश नहीं कि बांग्लादेश के बाद उसके एक और पड़ोसी देश में आइएस ने शांति भंग कर दी। श्रीलंका में हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां अवश्य ही सतर्क हुई होंगी। उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि नेशलन तौहीद जमात की जड़ें तमिलनाडु में भी होने का अंदेशा है। अंदेशा यह भी है कि इस संगठन का सरगना तमिलनाडु आता-जाता रहा है और उसे दक्षिण भारत से आर्थिक मदद भी मिलती रही है।

response@jagran.com

अथ श्री चुनाव ड्यूटी कथा

हास्य-व्यंग्य

शैलेश त्रिपाठी

चुनावी ड्यूटी कटवाने वालों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। कुछ तो ऐसा जाहिर करने में लगे हुए थे मानों वे चंद दिनों के मेहमान हैं

भगवान भी हैरान थे। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने वालों को उलाहना देने वाला रामप्रीत आज उनकी देहरी पर खड़ा था। उसने भगवान को लुभाने के लिए भी तमाम तरह के प्रलोभन देने शुरू कर दिए कि मन्नत पूरी होने पर वह कितने का प्रसाद, कितने की दक्षिणा और कहां पर केश चढ़ाने जाएगा। रामप्रीत की भक्ति-वंदना की भनक जैसे ही उनके कामरेड गुरु छोटेलाल को लगी तो चेले को अपनी लाइन पर वापस लाने के लिए वह भी मंदिर की ओर भागे।

छोटेलाल ने चेले के रातोंरात हृदय परिवर्तन की मंशा जाननी चाही तो उनके शिष्य ने धीरे से एक पर्ची उनकी ओर सरका दी। पर्ची पढ़ते ही गुरुजी को 'अनर्थ' का अंदाजा लग गया। वह सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने चेले की काहिलियत से भली-भांति वाकिफ थे। असल में रामप्रीत की ड्यूटी चुनाव में एक संवेदनशील बूथ पर लगा दी गई थी। इस पर छोटेलाल ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है? जवाब में रामप्रीत ने अपने दिवंगत फूफा की कहानी सुनाई जो बड़े उत्साह से मतदान कराने गए थे, लेकिन कभी वापस लौटे नहीं। उसने गुरुजी से गुहार लगाई कि कैसे भी मेरी ड्यूटी कटवाओ, क्योंकि मौत से ज्यादा तो मैं गांव में शौच के लिए लोटा लेकर जाने को लेकर डरा हूं। इस पर गुरु ने कहा कि आजकल तो मोबाइल टॉयलेट वैन आने लगी है। घबराए रामप्रीत ने कहा कि अरे वो तो और बड़ी मुसीबत है जिसकी तंगहाली के कुख्यात किस्से जगजाहिर हैं। वह बताने लगा कि चुनावी ड्यूटी में गए भारी देह वाले उनके मौसा कैसे उसमें फंस गए थे। तब अफवाह फैल गई कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई है तो शक ईवीएम पर गया, लेकिन असल में मामला सचल शौचालय में खराबी का था। निराश चेले को परेशान देख तिकड़मी गुरु ने दिमागी घोड़े दौड़ाए। जुगाड़ की दुनिया में जाने-माने नाम अपने परिचित रोशनलाल का नंबर लगाया जो बीस साल की सरकारी नौकरी में कई दफा चुनावी ड्यूटी के आदेश को बैरंग लौटा चुके थे। मगर इस बार चुनावी ड्यूटी का आदेश रोशनलाल की जिंदगी में भी अंधियारा ले आया। आदेश फाड़ने की शेखी बघारने का उनका वीडियो वायरल हो गया और उन्हें अवमानना के मामले में अंदर कर दिया गया। छोटेलाल ने फिर एक और महान मूर्ति का नंबर मिलाया। उन्होंने भी तमाम सिफारिशी फोन करा दिए, लेकिन चुनावी ड्यूटी रामप्रीत की कुंडली से गायब ही नहीं हुई। फिर उन्होंने विधि-सम्मत ड्यूटी कटवाने का एक फूलप्रूफ प्लान बनाया। इसके तहत एक मार्मिक आवेदन तैयार किया। खिला-पिलाकर डॉक्टर से लिखवा लिया कि श्रीमान रामप्रीत कई असाध्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और बीते दिनों एक आवारा सांड ने भी उन्हें फुटबॉल बना दिया। चार आदमी रामप्रीत को टांगकर चुनाव कार्यालय ले गए। वहां ड्यूटी कटवाने वालों की भीड़ जुटी हुई थी। कुछ तो ऐसा जाहिर कर रहे थे कि वे अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं। कुछ यह बता रहे थे कि चुनावी ड्यूटी किस तरह दुनिया का सबसे कठिन काम है। पता चला मेडिकल बोर्ड 'सघन' जांच करके फाइनल करेगा कि आवेदक ड्यूटी काटने लायक है या नहीं। तभी जांचकर्ता डॉक्टर ने प्रवेश किया जिसे देखते ही तमाम लोगों के तोते उड़ गए। असल में यह वही डॉक्टर साहब थे जिन पर इलाज के दौरान मरीजों पर सख्ती बरतने और लापरवाही के आरोप लग चुके थे। डॉक्टर कुछ पहलवान टाइप बंदों को साथ लाए थे। आते ही आदेश दिया कि हर आदमी को अपनी उम्र के हिसाब से दंड-बैठक लगानी होगी। सुनते ही मैदान साफ। रामप्रीत भी भाग खड़े हुए। घर आकर वह सोने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी की चिंता ही सताती रही।

ड्यूटी की तारीख करीब आती जा रही थी। अवसाद ने रामप्रीत को पकड़ लिया। इस बीच उसने कई दलालों की भी सेवाएं लीं जिन्होंने दलाली के बदले ड्यूटी कटवाने का दावा किया था। यह बात और थी कि पैसे लेने के बाद उनमें से ज्यादातर दलालों के फोन उठने बंद हो गए थे। चुनाव के ऐन पहले रामप्रीत के घर भारत सरकार का मुहर लगा एक सरकारी लिफाफा आया। उसने समझा कि शायद किसी दलाल ने काम करा दिया है। सो जल्दी से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि हमने बहुत बारीकी से आपके ड्यूटी काटने के आवेदन का अध्ययन किया और यह पाया कि एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आपने सरकार की आंखों में धूल झोंकने का अति निंदनीय कृत्य किया है और ऐसे कृत्य आप पहले भी करते रहे हैं। लिहाजा आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। इसके आगे रामप्रीत कुछ पढ़ नहीं सके।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

अमेरिका पर मंडराता खसरे का खतरा

* 25 अप्रैल 2019 तक के आंकड़े

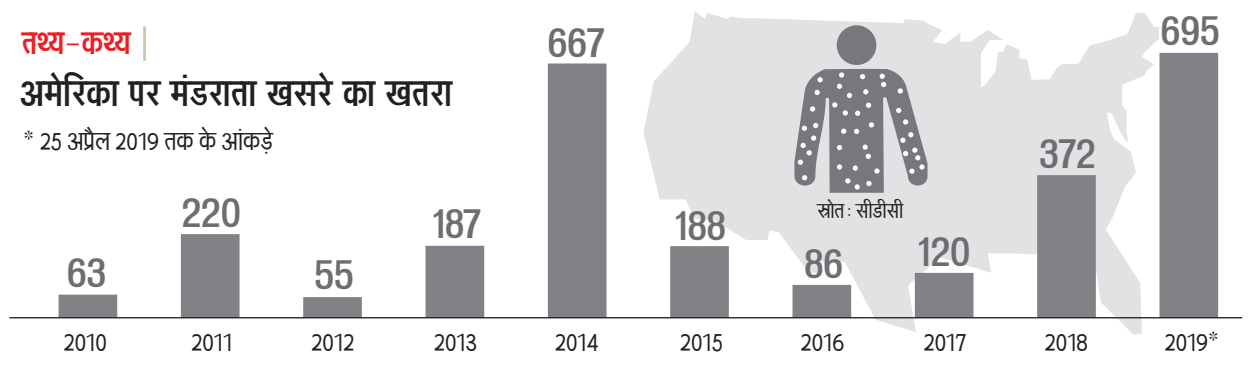

ऊर्जा

इच्छा शक्ति

प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शक्तियों का अकूत खजाना है। इन शक्तियों के माध्यम से वह जीवन की काया पलट सकता है। हमारे जीवन में विभिन्न तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन उनसे हमारा हौसला डिगना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति के भीतर कुछ करने की आकांक्षा उठती है तब असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सफलता का मूल बिंदु ही इच्छा शक्ति है। इसके दम पर व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। प्रत्येक मानव दृढ़ इच्छाशक्ति से चरित्रशक्ति में निखार लाए और तेजस्विता को बढ़ाए। शंका दुख का कारण है। उसमें निषेधात्मक विचारों के सर्प रेंगते रहते हैं। व्यर्थ की शंकाएं केवल कुकल्पनाओं को जन्म देती हैं एवं मैत्री के धागे को तोड़ती हैं। अक्सर देखने में आता है कि आज की भागदौड़ एवं तनाव भरी जिदंगी में लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं।

आप पर सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, बल्कि आपके परिवार, समाज का और राष्ट्र का भी अधिकार है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में इनका भी हाथ है। इसलिए आपकी इनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति ही नया सृजन कर सकता है। जो लोग पद और प्रतिष्ठा पाकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वे बहुत शीघ्र पतन की खाई में भी गिरते नजर आते हैं। हमें रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता के लिए अपनी ही गलतियों से सीख लेनी होगी, क्योंकि हमारी गलतियां ही हमारी असली शिक्षक हैं। गलतियों से सीख लेकर उनकी पुनरावृत्ति न करना ही विशिष्ट व्यक्तित्व की पहचान है।

भाग्य की सृष्टि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होती है कि वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य की दिशा को घुमा सकता है। भाग्य के भरोसे रहने वाला कोई भी महान नहीं बनता। सफलता के द्वार पर दस्तक देने के लिए चलते रहो-चलते रहो- का सूत्र जीवन में आत्मसात करना होगा। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है-सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण व्यक्ति की सृजन चेतना को जगाता है। जब तक दृष्टि सही नहीं होती तब तक व्यवहार भी अच्छा नहीं हो सकता। सही वस्तु को सही माने बिना सही दिशा का चुनाव भी नहीं हो सकता। दृष्टि को मिथ्या बनाए रखने वाले अनेक स्थानों से पदच्युत व दिशाभ्रमित हो जाते हैं।

ललित गर्ग

क्षमता दर्शाने वाली परियोजना

मुकुल व्यास

सीएसआइआर के नेतृत्व में इस पहल से सिद्ध हो जाएगा कि भारत भी संपूर्ण जीन-समूह को क्रमबद्ध करने में सक्षम है

भारत के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में रहने वाले करीब 1,000 युवाओं के जीन-समूह को क्रमबद्ध किया जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों की नई पीढ़ी को जीन-विज्ञान की उपयोगिता से अवगत कराना है। दुनिया में अनेक देशों ने अपने नागरिकों के नमूने के जीन-समूहों को क्रमबद्ध करना आरंभ किया है, ताकि उनके जीनों की विशिष्टताओं तथा रोगों से लड़ने की क्षमताओं या रोगों के प्रति उनकी कमजोरियों को निर्धारित किया जा सके।

यह प्रोजेक्ट दरअसल सरकार द्वारा प्रस्तावित एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके अंतर्गत कम से कम 10,000 भारतीय जीन-समूहों को क्रमबद्ध किया जाएगा। जीन-समूहों के नमूना संग्रह के लिए जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है, वे देश की आबादी की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अधिकांश कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राएं हैं जो जीव-विज्ञान या उससे संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। सीएसआइआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आइजीआइबी) के एक वैज्ञानिक का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महज लोगों के नमूने ही नहीं एकत्र किए जाएंगे। हम अधिक से अधिक छात्रों के पास जाएंगे और उन्हें जीनोमिक्स के बारे में शिक्षित करेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम भी बनाएंगे जिसके जरिये वे अपने जीन-समूहों द्वारा दी गई जानकारी हासिल कर सकेंगे। अभी जीन-विज्ञान भारत के संपन्न वर्ग तक ही सीमित है, लेकिन नए कार्यक्रम से ऐसी जानकारियों का लाभ ग्रामीणों को भी मिलेगा। आज भारत में जिस तरह लोग सीटी स्कैन के बारे में जानते हैं, ठीक उसी तरह वे जीन-नक्शों की उपयोगिता को भी समझने लगेंगे।

जीन-समूहों को रक्त के नमूनों से क्रमबद्ध किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक अधिकांश राज्यों में कम से कम 30 शिविर लगाएंगे। जिस व्यक्ति के जीन क्रमबद्ध किए जाएंगे उसे एक रिपोर्ट दी जाएगी। नमूने देने वाले व्यक्ति को ऐसे जीनों के बारे में बताया जाएगा जिनकी मौजूदगी से कुछ दवाएं कम असर करती हैं। मसलन एक खास जीन की मौजूदगी से कुछ लोगों पर क्लोपिडोग्रेल नामक दवा का असर कम होता है। दिल के दौरे या पक्षाघात को रोकने के लिए यह दवा दी जाती है। आइजीआइबी के वैज्ञानिक ने कहा कि हम रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी को साझा नहीं करेंगे। कुछ मामलों में जीन और बीमारी के बीच संबंध काफी कमजोर होता है। अमुक व्यक्ति इस तरह की जानकारी के लिए अपने डॉक्टर के माध्यम से अनुरोध कर सकता है, क्योंकि अनेक रोग एक जीन की गड़बड़ी की वजह से होते हैं और उनका कोई इलाज संभव नहीं है। ऐसी सूचनाएं सिर्फ उपयुक्त परामर्श के बाद ही साझा की जानी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जीन को क्रमबद्ध करने का काम आइजीआइबी और सीसीएमबी में किया जाएगा। इससे यह साबित हो जाएगा कि भारत भी संपूर्ण जीन-समूह को क्रमबद्ध करने में सक्षम है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

चिंता का सबब

जबलपुर के सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह शायद चुनाव का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आतंकवाद को लेकर एक बयान पर वह गलती कर चुके हैं। मानों इतना ही काफी नहीं है। लगता है कि वह संगठन के स्तर पर भी अनजान हैं। हाल में केंद्र के एक बड़े नेता का मध्य प्रदेश दौरा हुआ था। संयोग से उन्हें जबलपुर ही जाना था और वहां उनका स्वागत करने के लिए राकेश सिंह भी मौजूद थे। लेकिन स्वागत की गर्मजोशी के बजाय वह शिकायत लेकर आए थे कि उनके दौरे की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। यह अचरज की बात है कि लंबे समय से सक्रिय राजनीति में मौजूद सांसद जी को शायद यही नहीं पता था कि चुनाव में स्टार प्रचारकों का दौरा प्रदेश के आग्रह पर ही लगता है। सांसद महोदय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्हें पता नहीं था तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि उनका संगठन उन्हें इस तरह क्यों नजरअंदाज कर रहा है। जब उन्हें यह बताया गया तो उनके माथे पर और बल पड़ गया। दरअसल यह चिंता का सबब है कि चुनाव बाद क्या होगा।

पिक्चर अभी बाकी है..

राजनीति के रंगमंच से कलाकारों का जुड़ाव वैसे तो कोई नई बात नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक दल ऐसे चेहरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में रहते है। पर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पिछले दिनों जिस तरह से बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे, गायक, कलाकार और खिलाड़ी जुड़े है, उसे लेकर बाकी राजनीतिक दलों की नींदें जरूर उड़ी हुई हैं। वजह कलाकारों की लोकप्रियता भी है। फिलहाल पार्टी के पास मौजूदा समय में एक पूरी फिल्म की टीम है। जिसमें हीरो, हीरोइन, गायक सभी हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कलाकारों का यह जमघट पार्टी को कुछ फायदा पहुंचाता है, या फिर बस एक राजनीतिक स्टंट ही बनकर रह जाएगा। फिलहाल क्या होगा, अभी से यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।

देर आए, दुरुस्त आयद

पिछले कुछ वर्षों में गौ माता बहुत चर्चा में रही है। कई बार यह राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बना और सरकार की तरफ से दावा भी खूब किया गया कि गोरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाया गया। कामधेनु आयोग का गठन भी किया गया जिसके बारे में बताया जा रहा है यह गौ सेवा का सबसे बड़ा अभियान है, लेकिन सरकारी बाबुओं की सुस्ती का आलम यह है है कि पांच वर्ष बीत जाने और आम चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद उन्हें याद आया कि गौ सदन और गौशाला का विषय कृषि मंत्रालय के पास था ही नहीं। यह विषय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन था। बहरहाल, आनन-फानन में अप्रैल के पहले हफ्ते में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई और पर्यावरण मंत्रालय से इसे कृषि मंत्रालय के पशुधन विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

कॉफी टेबल बुक

नेताओं के बारे में एक बात मशहूर है कि वे प्रचार पाने का कोई मौका नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही आजकल उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने एक कॉफी टेबल किताब प्रकाशित कराई है जो आजकल राजधानी के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन मंत्री महोदय ने रंगबिरंगी कॉफी टेबल बुक के लिए जापानी बुखार जैसे संजीदा विषय को चुना है। बताया जाता है कि इसे छपवाने के लिए राज्य सरकार ने अच्छी-खासी रकम खर्च की है। इसमें जापानी एंसेफालाइटिस के बारे में तो बताया ही गया है, नेताओं की तस्वीरों की भी भरमार है। मंत्री महोदय ने लखनऊ में इसका वितरण किया है और अब लुटियंस जोन में बैठने वाले प्रभावशाली लोगों के पास भी इसकी प्रतियां भेजी हैं। बहरहाल यह खतरनाक बीमारी भले ही जड़ से खत्म न हुई हो, लेकिन कॉफी टेबल बुक के बहाने नेताजी को प्रचार पाने का मौका जरूर मिल रहा है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।